

“ पहले मुख्य समाचार ”

- डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख व भू-प्रशासन चुनौतियों पर आज से मनाली में राष्ट्रीय कार्यशाला का होगा आयोजन— मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे शिरकत।
- भाजपा विधायक दल की बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर बनाई गई रणनीति, भाजपा का आरोप— पंचायतीराज चुनाव को लेकर सरकार और चुनाव आयोग में टकराव।
- राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए लागू किया नया फार्मूला।
- सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में पदयात्राओं का दौर जारी। और
- प्राकृतिक खेती से सुरक्षित खाद्यान्न और पर्यावरण संरक्षण को मिल रहा बढ़ावा—किसानों की बढ़ रही आय।

अब समाचार विस्तार से.....

राष्ट्रीय कार्यशाला

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग और हिमाचल प्रदेश सरकार के भू-अभिलेख निदेशालय के सहयोग से आज से मनाली में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति की उच्च-स्तरीय समीक्षा होगी। इसमें 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव, राजस्व सचिव, भू-अभिलेख निदेशक और निपटान आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। वे भू-प्रशासन संबंधी चुनौतियों पर विमर्श करेंगे और इस क्षेत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे।

विधायक दल की बैठक

प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक कल शाम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में बिहार चुनाव में एनडीए को मिली जीत पर एक बधाई प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र में प्रदेश सरकार को अलग-अलग विषयों पर घेरने की योजना बनाई गई। बैठक की जानकारी देते हुए विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को जिस प्रकार प्रदेश सरकार टालने का प्रयास कर रही है उससे चुनाव आयोग और सरकार के बीच टकराव की स्थिति नज़र आ रही है। रणधीर शर्मा ने इसे प्रदेश में संवैधानिक संकट बताया।

प्राकृतिक खेती

प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर सुरक्षित खाद्यान्न पैदा करने तथा पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। हमीरपुर से प्राकृतिक खेती पर पेश है एक रिपोर्ट....

कर्मचारी पेंशन

राज्य सरकार ने प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए नया फार्मूला लागू कर दिया है। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने एक अनुपात पांच का विशेष फार्मूला अपनाने के निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पात्र कर्मचारियों को 60 दिन के भीतर ओपीएस विकल्प चुनना होगा और सरकार के योगदान और लाभांश को जमा करवाने के साथ पेंशन के लिए आवेदन करना होगा। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों दैनिक वेतन आधार पर लंबे से कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए पेंशन पाने का रास्ता साफ हुआ है।

पद यात्रा

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हिमाचल में भी विभिन्न क्षेत्रों में पदयात्राएं निकाली जा रही हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा माई भारत के सहयोग कल शिमला में एक एकता मार्च का आयोजन किया गया। सांसद सुरेश कश्यप के नेतृत्व में इस यात्रा में सैंकड़ों युवाओं, एनसीसी और एन.एस.एस. कैडेट्स के अलावा स्थानीय लोगों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना और एकता की भावना को मजबूत करना है।

इसी कड़ी में आज सोलन विधानसभा क्षेत्र के चंबाघाट, कसौली विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी और सराहां में एक पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा।

मौसम

प्रदेशभर में लगातार मौसम साफ बना हुआ है। आंकड़ों के अनुसार नवंबर माह में अब तक 90 प्रतिशत सामान्य से कम वर्षा दर्ज हुई है, जिससे प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। बारिश न होने के बावजूद उंचाई वाले क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते 24 घंटों में राज्य के 24 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सैल्सियस से कम रहा।

इस बीच अत्याधिक ठंड और सड़क पर पानी जमने के कारण रोहतांग दर्रा आज से पर्यटकों के लिए आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार ग्रांफू से रोहतांग और जिंजिंजिंबार से सरचू तक वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं है। देश-विदेश के पर्यटकों को रोहतांग दर्रे का दीदार करने के लिए अब अगले 6 महीने का इंतजार करना होगा।

और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से

आज समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में लागू डिजास्टर एक्ट के कारण नहीं कर पाए निर्देशों का पाल-पंचायती राज चुनाव में उपायुक्तों ने दिया जवाब। दैनिक जागरण का शीर्षक है पंचायत सीमा बदलाव रोकने पर विवाद, सरकार ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र।

दैनिक भास्कर की एक खबर है हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर दस हजार का जुर्माना लगाया, अदालत में नेशनल हाईवे की सही तस्वीर नहीं की पेश।

मौसम पर दिव्य हिमाचल की खबर है 24 स्थानों पर न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम।

मुख्य समाचार एक बार फिर''

- डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख व भू-प्रशासन चुनौतियों पर आज से मनाली में राष्ट्रीय कार्यशाला का होगा आयोजन— मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे शिरकत।
- भाजपा विधायक दल की बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर बनाई गई रणनीति, भाजपा का आरोप— पंचायतीराज चुनाव को लेकर सरकार और चुनाव आयोग में टकराव।
- राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए लागू किया नया फार्मूला।
- सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में पदयात्राओं का दौर जारी। और
- प्राकृतिक खेती से सुरक्षित खाद्यान और पर्यावरण संरक्षण को मिल रहा बढ़ावा—किसानों की बढ़ रही आय।